

हरित ऊर्जा टैरिफ में कमी से निर्यातकों को राहत मिलेगी

प्रोत्साहन

रोहित मिश्र

लखनऊ। अमेरिकी टैरिफ के बाद मुसीबतों से जूझ रहे निर्यातकों के लिए उत्तर प्रदेश की बिजली दरों में राहत का इंतजाम किया गया है। नियामक आयोग ने बीते दिनों जो बिजली की नई दरें तय की हैं, उनमें आम उपभोक्ताओं के लिए तो दरें स्थिर रखी गई हैं, जबकि ग्रीन एनर्जी टैरिफ में कमी की गई है।

विदेशों में अपना सामान बेचने वाले उद्योग ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बदले में उन्हें वहां सब्सिडी मिलती है। अमेरिका ने भारत पर 25

प्रतिशत का टैरिफ लगाया था, जिसमें बाद में 25 प्रतिशत का और इजाफा कर दिया था।

इस तरह से भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ अमेरिका ने लगा रखा है। इससे अमेरिका में अपने उत्पादों का निर्यात करने वाले उद्योगों को झटका लगा है और वे नया बाजार तलाश रहे हैं। इस बीच सरकार की कोशिश है कि उद्योगों को हर स्तर पर राहत दी जाए ताकि उनका निर्यात प्रभावित न हो। बीते दिनों नियामक आयोग द्वारा जारी वर्ष 2025-26 की दरों में ग्रीन एनर्जी टैरिफ में कमी की गई है। पहले इसकी दरें 0.36 रुपये प्रति यूनिट हुआ करती थी जो इस साल

ग्रीन एनर्जी के लिए करना होता है अतिरिक्त भुगतान



ग्रीन एनर्जी के लिए उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान करना होता है। ग्रीन एनर्जी टैरिफ वह दरें हैं, जिसका भुगतान सामान्य बिजली दरों के ऊपर उपभोक्ताओं को करना होता है। वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश में एचवी श्रेणी के उपभोक्ताओं को 22,174.24 मिलियन यूनिट बिजली सप्लाई की जाएगी, जिससे 18,769.13 करोड़ रुपये का राजस्व आएगा। लिहाजा, इस तरह से औसत बिलिंग दर 8.46 रुपये प्रति यूनिट आने का अनुमान है।

के लिए घटाकर 0.34 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है। इससे ग्रीन एनर्जी खरीदने वाले उद्योगों को कम पैसा अदा करना होगा। यह दरें हाई वोल्टेज (एचवी) श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू होंगी।

इस श्रेणी में ऐसे बड़े उद्योग, बड़े वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और संस्थान आते हैं, जिन्हें 33 केवी या इससे ज्यादा वोल्टेज की ऊर्जा की आवश्यकता होती है।



बड़े उद्योग और तमाम वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, जो विदेशों में अपने उत्पादों का निर्यात

करते हैं, उन्हें ग्रीन एनर्जी खरीदनी पड़ती है। उनके कुल बिजली इस्तेमाल में ग्रीन एनर्जी का एक कोटा होता है। इसके एवज में उन्हें उत्पादों पर विदेशों में सब्सिडी भी मिलती है। इस साल इन दरों में कमी की गई है।
एके शर्मा, ऊर्जा मंत्री